Toppersnotes®
Unleash the topper in you

SSC - CGL

संयुक्त स्नातक स्तर

कर्मचारी चयन आयोग

भाग – 5

सामान्य अध्ययन

SIERRA INNOVATIONS

SSC - CGL

S.N.	Content	P.N.
	भारत का भूगोल	
1.	भारत का विस्तार	1
2.	भारत के भौगोलिक भू–भाग	6
3.	भारत का अपवाह तंत्र	35
4.	जैव विविधता	50
6.	भारत की मृदा	58
7.	भारत में खनिजों का वितरण	64
8.	कृषि	75
9.	विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य	86
	भारत का इतिहास व राजव्यवस्था	
1.	प्राचीन इतिहास	95
	• सिन्धु घाटी सभ्यता	97
	• वैदिक काल	103
	• बौद्ध धर्म	107
	• जैन धर्म	109
	• मौर्य वंश	112
	• पुष्यभूति वंश	118
	• संगम वंश	119
	• त्रिपक्षीय संघर्ष	122
2.	मध्यकालीन भारत	126
	• सल्तनत काल	126
	• मुगल काल	137
	• विजयनगर साम्राज्य	152
3.	आधुनिक भारत का इतिहास	156
	• भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन	156
	• मराठा शक्ति का उत्कर्ष	163

	• देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति	169
	• अंग्रेजो की भू–राजस्व पद्धतियाँ	172
	• आग्ल सिख का संघर्ष	177
	• गवर्नर व वायसराय	177
	• 1857 की क्रान्ति	186
	• महत्वपूर्ण विद्रोह	189
	• राष्ट्रीय आन्दोलन	198
	• कांग्रेस अधिवेशन	199
	• प्रमूख व्यक्तित्व	224
4.	भारतीय संविधान	226
	• भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास	226
	• संविधान के भाग	234
	• राष्ट्रपति की शक्तियाँ	256
	• लोकसभा	268
	• न्यायपालिका	283
	• संविधान संशोधन	292
	अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र	304
2.	राष्ट्रीय आय	305
3.	मुद्रास्फीति	306
4.	बैंकिंग	309
5.	राजकोषीय नीति एवं बजट	317
6.	बेरोजगारी एवं गरीबी	321
7.	पंचवर्षीय योजनायें	323

भारतीय भूगोल

(Indian Geography)

भारत का विस्तार

- भारत में उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी से अधिक है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशान्तर के बीच दूरी कम होती जाती है परन्तु अक्षांशों के बीच दूरी समान रहती है ।
- भारत का क्षेत्रफल = 3287263 किमी.^{2} = लगभग 32.8 लाख किमी.^{2}
- विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है ।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7th स्थान है ।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश–
  - रूस
  - कनाडा
  - चीन
  - यू.एस.ए
  - ब्राजील
  - ऑस्ट्रेलिया
  - भारत
  - अर्जेन्टिना
  - कजाकिस्तान
  - अल्जीरिया

- भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड है जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है ।
- नवीनतम आंकाडो के अनुसार 2021 मे भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड हो चुकी है ।
- जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है ।
- भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल, चीन तथा भूटान देश है तथा पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है और दक्षिण में श्रीलंका एवं हिन्द महासागर से घिरा है ।
- भारत में अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाडी में स्थित है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है ।
- भारत का दक्षिणतम बिन्दु इन्दिरा पाइंट (निकोबार) 6°45' उत्तरी अक्षांश है जिसे पिग्मेलियन प्वाइंट भी कहते है ।
- अरावली की पहाडियाँ राजस्थान में स्थित है । यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है । इस पहाडी की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट आबू पर स्थित गुरुशिखर है । इसकी ऊँचाई 1722 मी. है ।
- विन्ध्याचल का पठार झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्यों में है । यह परतदार चट्टानों का बना है । विन्ध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ।
- मैकाले पठार छत्तीसगढ राज्य में स्थित है । मैकाले पहाडी का सर्वोच्च शिखर अमरकण्टक है । इसकी ऊँचाई 1048 मी. है । यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है ।
- सतपुडा की पहाडियाँ मध्य प्रदेश में है । ये ज्वालामुखी चट्टानों की बनी है । इनकी सबसे ऊँची चोटी धूपगढ (1350 मी.) है ।

- दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है । यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना है । यह काली मिट्टी का क्षेत्र है । इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्रि की पहाडी है । सह्याद्रि की सबसे ऊँची चोटी कल्सुबाई है ।
- धारवाड का पठार कर्नाटक राज्य में है । यह परिवर्तित चट्टानों का बना है । इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाडी तथा ब्रह्मगिरि की पहाडी है ।

भारत का भौगोलिक विस्तार

- बडे राज्य
  - राजस्थान (3.42 लाख Km^2)
  - मध्यप्रदेश (3.08 लाख Km^2)
  - महाराष्ट्र (3.07 लाख Km^2)
- छोटे राज्य
  - गोवा – (3702 Km^2)
  - सिक्किम – (7096 Km^2)
- बडे जिले
  - कच्छ – (45,652 Km^2)
  - लेह – (45,110 Km^2)
  - जैसलमेर – (38,401 Km^2)
- छोटा जिला
  - माही (09 Km^2) (पाण्डिचेरी)

अक्षांश का प्रभाव

- भारत का अक्षांशीय विस्तार 30° होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा तथा वनस्पति से संबंधित विविधता पाई जाती है ।
- कर्क रेखा ($23\frac{1}{2}°N$) भारत को दो प्रमुख भागों में बाँटती है– भारत का दक्षिणी भाग ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में स्थित है ।
- भारत में उष्ण कटिबन्धीय मानसून जलवायु पाई जाती है क्योंकि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत साइबेरिया से जाने वाली ठण्डी पवनों को रोकता है ।
- कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से होकर गुजरती है ।

देशान्तर का प्रभाव

- भारत का देशान्तरीय विस्तार 30° होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम भाग के बीच 2 घंटे का अन्तर पाया जाता है ।
- 82½° पूर्वी देशान्तर को भारत की स्थानीय समय गणना के लिए एक मानक देशान्तर के रूप में चुना गया है । यह रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है ।
- भारत का मानक समय **GMT** से 5½ घंटे आगे है ।

- 82½° पूर्वी देशान्तर निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है :-

Border of India

1. स्थलीय सीमा

- भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15200 किमी. (15106.7 किमी.) है ।
- भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों को स्पर्श करती है :-

		NCERT के अनुसार
1.	बांग्लादेश = **4096.7 km** (सर्वाधिक)	4096 किमी
2.	चीन = **3488 km**	3917 किमी
3.	पाकिस्तान = **3323 km**	3310 किमी
4.	नेपाल = **1751 km**	1752 किमी
5.	म्यांमार = **1643 km**	1458 किमी
6.	भूटान = **699 km**	587 किमी
7.	अफगानिस्तान = **106 km** (सबसे कम)	80 किमी यह सीमा अप्रत्यक्ष रूप से लगती है ।

देश तथा सीमा पर स्थित भारतीय राज्य			
क्र. सं.	देश	कुल संख्या	भारतीय राज्य
1.	चीन	5	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
2.	नेपाल	5	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम
3.	बांग्लादेश	5	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
4.	म्यांमार	4	अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम
5.	पाकिस्तान	4	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर
6	भूटान	4	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश
7.	अफगानिस्तान	1	जम्मू कश्मीर (पाक अधिकृत कश्मीर)

- भारत-पाकिस्तान की सीमा रेखा = रेडक्लिफ रेखा है जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की थी
- भारत-चीन की सीमा रेखा = मैकमोहन जिसे 1914 ई. मे शिमला मे निर्धारित की गई ।
- भारत-अफगानिस्तान की सीमा रेखा = डूरन्ड रेखा

2. जलीय सीमा

- मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किमी. है ।
- भारत की कुल जलीय सीमा = 7516.6 किमी.
  Mainland = 5422.6 km & Island = 2094 km

- सर्वाधिक लम्बी तटीय रेखा वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	तटरेखा (किमी.)
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1962
गुजरात	1215
आन्ध्र प्रदेश	970
तमिलनाडु	907
महाराष्ट्र	652
लक्षद्वीप	132
पुडुचेरी	47
दमन एवं दीव	42

तटवर्ती/सीमावर्ती सागर

1. सीमावर्ती सागर **(Territorial Sea)**
2. संलग्न सागर **(Contiguous Sea)**
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र **(Exclusive Economic Zone)**

1. सीमावर्ती सागर

- यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित है ।
- इस क्षेत्र में भारत का एकाधिकार है ।

2. संलग्न सागर

- यह क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक स्थित है ।
- इस क्षेत्र में भारत के पास वित्तीय अधिकार है ।
- यहाँ भारत सीमा शुल्क **(Custom Duty)** वसूल सकता है ।

3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र

- यह क्षेत्र आधार रेखा से 200**nm** तक स्थित है।
- इस क्षेत्र में भारत के पास आर्थिक अधिकार है तथा यहाँ भारत संसाधनों का दोहन, द्वीप निर्माण तथा अनुसंधान आदि कर सकता है ।
  <u>उच्च सागर</u> :- यहाँ सभी देशों का समान अधिकार होता है ।

तटवर्ती सीमा के लाभ

- तटवर्ती सीमा दक्षिण भारत में समकारी जलवायु **(Moderate Climate)** का निर्माण करती है ।
- तटवर्ती सीमा बन्दरगाहों के निर्माण के लिए उपयोगी है । इन बन्दरगाहों के माध्यम से आयात-निर्यात व्यापार किया जाता है ।

- तटवर्ती सीमा भारत को विभिन्न देशों से जोडती है ।
- पर्यटन की दृष्टि से भी यह उपयोगी होती है ।
- महासागरीय संसाधनों तक तटवर्ती सीमा पहुँच बनाती है ।
- सुरक्षा की दृष्टि से भी तटवर्ती सीमा महत्वपूर्ण है ।

तटवर्ती सीमा के नुकसान

- सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पडता है ।
- समुद्री लुटेरों, तस्करी आदि का भी डर बना रहता है ।
- तटवर्ती सीमा के रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यय करना पडता है ।

<u>निष्कर्ष</u> :- तटवर्ती सीमा के नकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद यह भारत के लिए लाभकारी है ।

भारतीय उपमहाद्वीप **(Indian Subcontinent)**

- उपमहाद्वीपीय उस भाग को कहा जाता है जो महाद्वीप में अपनी एक पृथक पहचान रखता हो ।
- भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से भारत एशिया के अन्य देशों से पृथक पहचान रखता है ।
- भारत के उत्तरी भाग में पर्वत स्थित है जैसे - हिन्दुकुश, सुलेमान, हिमालय, पूर्वांचल तथा पूर्व में अराकानयोगा जो भारत को एशिया के मुख्य भूभाग से पृथक करते है ।
- भारत के दक्षिणी भाग में महासागरीय क्षेत्र स्थित है जो भारत तथा पडौसी देशों को पृथक पहचान दिलाता है ।
- भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश सम्मिलित है:-

➢ भारत	➢ भूटान
➢ पाकिस्तान	➢ बांग्लादेश
➢ अफगानिस्तान	➢ श्रीलंका
➢ नेपाल	➢ मालदीव

प्राचीन इतिहास

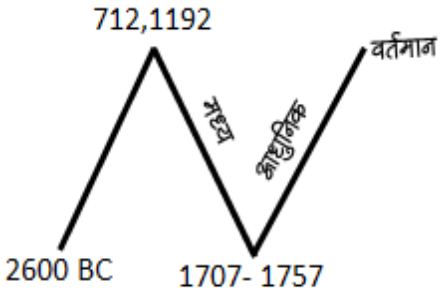

कालक्रम

1. 2600 BC – 1900 BC
   सिन्धुघाटी सभ्यता
2. 1900 BC – 1500 BC
   ----
3. 500 BC – 1000 BC
   ऋग्वैदिक काल
4. 1000 BC – 600 BC
   उत्तरवैदिक काल
5. 600 BC – 321 BC
   महाजनपद काल (बौद्ध, जैन)
6. 321 BC – 184 BC
   मौर्य काल
7. 184 BC – 321 AD
   मौर्योत्तर काल
8. 319 AD – 550 AD
   गुप्तकाल
9. 606 AD – 647 AD
   हर्षवर्द्धन
10. 750 AD – 1000 AD
    राजपूत काल
11. 1192 (1206) – 1526 AD
    सल्तनत काल
12. 1526 AD – 1707 (1858)
    मुगल काल
13. 1707 (1757)
    वर्तमान आधुनिक काल

प्राचीन काल में भारत इतिहास

- इतिहास शब्द ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है खोज अथवा छानबीन ।
- इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है । जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणित तिथि उपलब्ध है ।
- ग्रीक विद्वान हैरोडोट्स ने इतिहास की प्रथम पुस्तक "हिस्टोरिका" लिखी ।
- हैरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है ।
- इतिहास को जानने के लिए निम्न स्त्रोत है ।
  1. पुरातात्विक स्त्रोत
  2. साहित्य स्त्रोत
  3. विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत ।

अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम निम्न प्रकार बाँट सकते हैं –

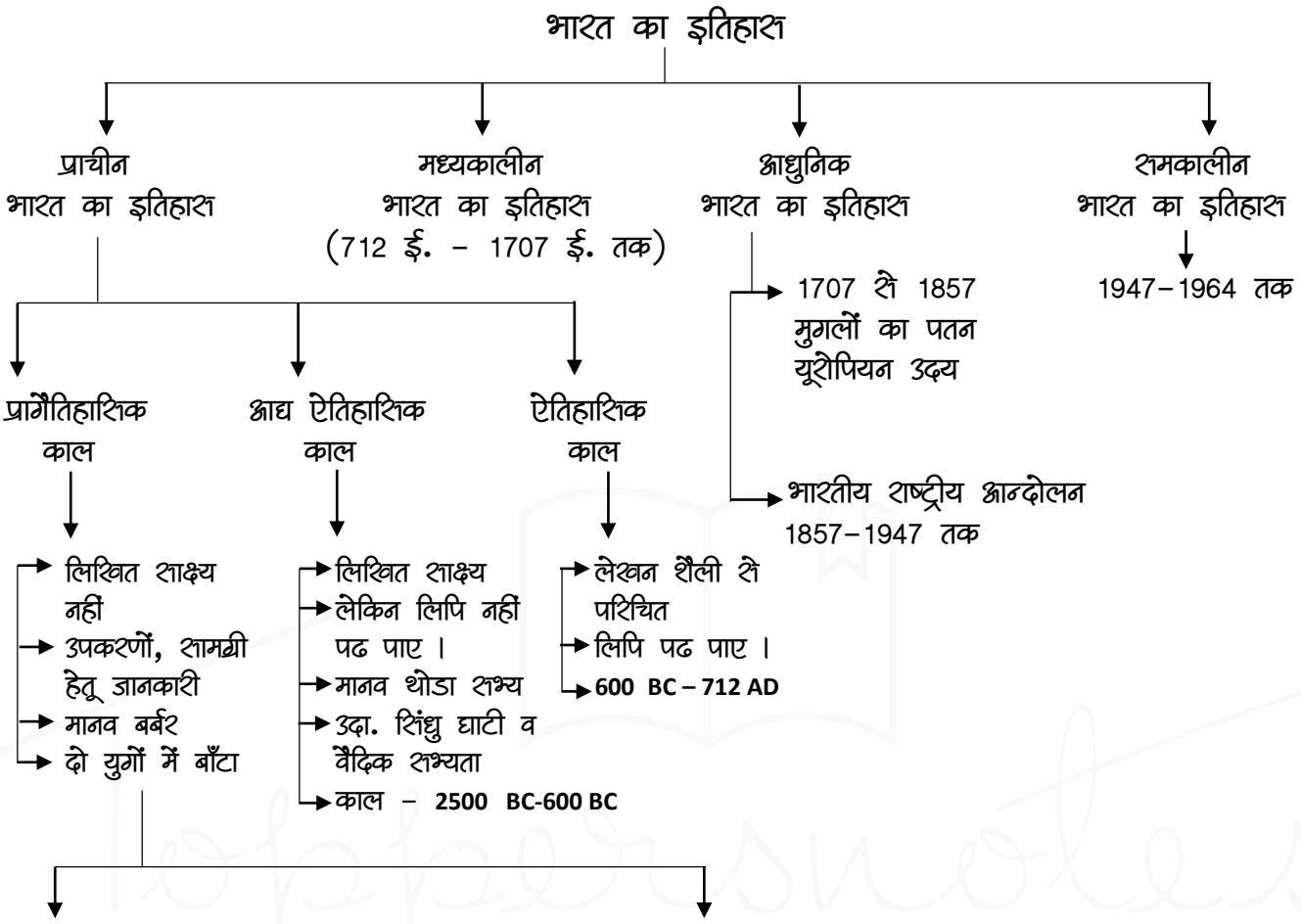

पुरा पाषाण काल (5 लाख BC – 10000 BC)

- निम्न पाषाण काल
- मध्य पुरापाषाण काल
- उच्च पुरापाषाण काल

मध्य पाषाण काल (10,000 - 8000 BC)

उत्तर/पाषाण काल (8000 BC - 6000 BC तक)

पुरापाषाण काल

- कोर संस्कृति, फलक संस्कृति एवं ब्लैड संस्कृति का उदय ।
- आधुनिक मानव होमो सेपियन्स का उदय ।
- मानव का आग जलाना ।
- इस काल में चापर - चौपिंग संस्कृति का उदय, डी एन वाडिया ने खोज की, यह उत्तर भारतीय संस्कृति है ।
- दक्षिण भारत की संस्कृति हैण्ड - एक्स संस्कृति है इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की ।
- चापर-चौपिंग एवं हैण्ड डैस संस्कृति (उत्तर एवं दक्षिण) मिलन स्थल चौतरान (जम्मू कश्मीर) है ।

प्रमुख स्थल

भीम बेटका - शैलाश्रय चित्रों के प्रसिद्ध (M.P)
डीडवाना (राजस्थान) - हथनौरा

मध्य पाषाण काल

- इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते है । छोटे-छोटे पाषाण उपकरणों के कारण ।
- मानव ने इस काल में सर्वप्रथम पशु पालन करना सीखा ।
- पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है । बागौर (राजस्थान) एवं आदमगढ (MP)
- इस मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता हैं ।
- मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल सराय नाहर यू.पी. हैं ।

उत्तर/नव पाषाण काल

- सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द दिया ।
- गार्डन चाइल्ड ने इस काल को "नव पाषाणिक क्रांति" कहा ।
- ली मेंसियर ने उत्तर भारत में नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- नेविलियन फ्रेंजर ने दक्षिण भारत से नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- मानव ने कृषि करना सीखा ।
- वृहद पैमाने पर पशुपालन एवं ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिले ।

प्रमुख स्थल

1. मेहरगढ (पाक) - नव पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल ।
   8000 BC पूर्व कृषि के साथ साक्ष्य मिलें ।
2. कोल्डी हवा (यूपी) - 6000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिलें ।
3. बुर्जहोम एवं गुफ्कराल (J&K) बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं ।

नोट -
प्रागैतिहासिक काल के जनक भारत में डॉ. प्राइम रोज थे । जिन्होंने लिंगसुगुर (कर्नाटक) से पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे ।
नव पाषाण काल में दक्षिण भारत की प्रमुख फसल रागी थी ।

सिन्धु घाटी सभ्यता

- परिचय
- विस्तार
- कालक्रम
- निवासी
- नगर नियोजन
- महत्वपूर्ण नगर
- लिपि
- पतन
- अन्य महत्वूर्ण तथ्य

परिचय

सिंधु घाटी सभ्यता

- 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस मोहनजोदडों की खोज की ।
- इस सभ्यता के स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे थे । अतः इस घाटी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पडा ।

सरस्वती नदी घाटी सभ्यता

- आजादी के बाद खोजे गए सर्वाधिक स्थल इस नदी क्षेत्र में हैं । अतः इसका नाम सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा हैं ।

कांस्य युगीन सभ्यता

- उत्खनन में कांस्य के बर्तन या उपकरण अधिक मिलें ।

नगरीय सभ्यता

- सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत एवं समृद्ध नगरीय सभ्यता है । यहाँ बडे - बडे नगरों का उदय हुआ था ।

विस्तार

- अफगानिस्तान
- पाकिस्तान
- भारत

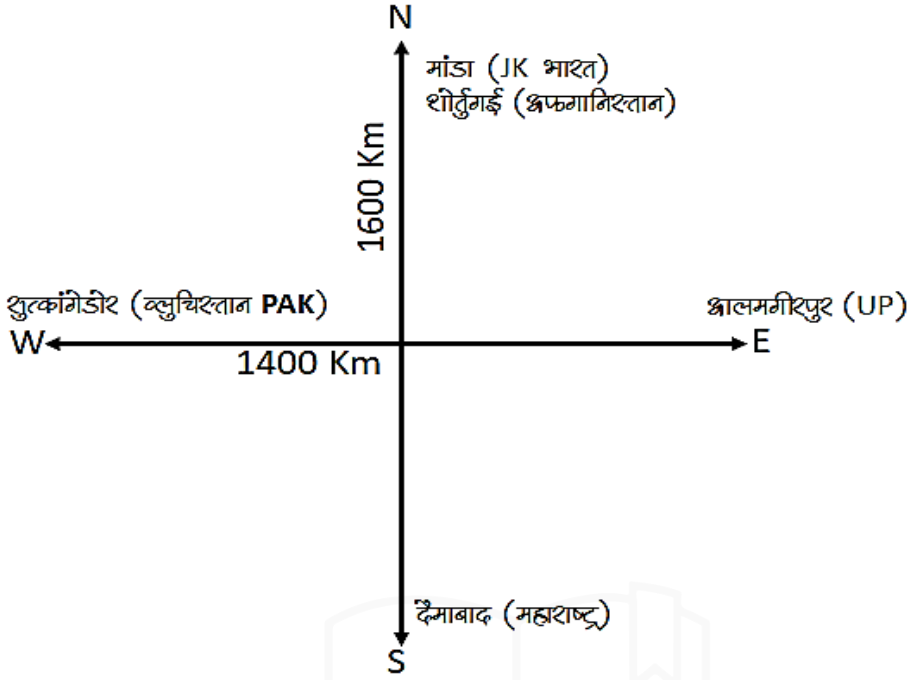

1300 किमी समुद्री सीमा

नोट –

- अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र दो स्थल थे । शार्तगोई एवं मुंडीगॉक है ।
- शार्तगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं ।
- सिंधु घाटी सभ्यता मिश्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बडी थी जबकि मिश्र की सभ्यता से 20 गुना बडी थी ।
- आजादी से पूर्व खोजे समस्त स्थल पाकिस्तान में चले गये । भारत में केवल दो स्थल रहे, रंगपुर (गुजरात) और कोटला निहंगखां (रोपड पंजाब)
- भारत का सबसे बडा स्थल राखीगढी (हरियाणा) है, दूसरा बडा स्थल धौला वीरा (गुजरात) है ।
- पिग्गट ने हडप्पा एवं मोहनजोदडों को सिन्धु सभ्यता की जुडवाँ राजधानी बताया है ।
- बडे नगर (पाकिस्तान)
  - हडप्पा
  - मोहनजोदडों

कालक्रम

- जॉन मार्शल – 3250 BC – 2750 BC
- माधोस्वरूप वत्स – 3500 BC – 2700 BC
- रेडियोकार्बन पद्धति – 2300 BC – 1750 BC
- एनसीआरटी – 2500 BC – 1750 BC
- फेयर सर्विस – 2000 BC – 1500 BC
- अर्नेस्ट मैके – 2800 BC – 2500 BC

निवासी

यहाँ से प्राप्त कंकालों के आधार पर चार प्रजातियों में बाँटा जा सकता है ।

1. भूमध्य सागरीय
2. अल्पाईन
3. मंगोलायड
4. प्रोटो ऑस्ट्रालायड

सर्वाधिक प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है ।

नगर नियोजन

- नगर दो भागों में विभाजित – पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग । पश्चिमी भाग दुर्ग था, पूर्वी भाग सामान्य नगर था ।
- पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे तथा पूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहते थे ।
- सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान है ।
- सिन्धु घाटी के समकालीन सभ्यताओं में इस विशेषता का अभाव ।
- नगर परकोटे युक्त होते थे ।
- घरों के दरवाजे मुख्य सडक की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे । केवल लोथल में मुख्य सडक की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे ।
- कालीबंगा दोहरे परकोटे युक्त है । जबकि चन्हुदडो में कोई परकोटा नहीं ।
- धौलावीरा तीन भागों में विभक्त है । पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्यमा ।
- लोथल एवं सुरकोटडा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग दोनों ही एक ही परकोटे से घिरे हुए है ।
  - सबसे चौडी सडक 10 मीटर (मोहनजोदडों) की मिलती है जो कि सम्भवतः राजमार्ग रहा होगा ।
  - घरों में उत्कृष्ट नाली व्यवस्था (जल निकासी हेतु)
  - बडी नालियों को ढक कर रखते थे ।
  - भवन के अन्दर सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोईघर, 1 विद्यालय स्नानागार एवं कुआँ होता था ।
  - कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे । ईंट का आकार – 1 : 2 : 4
  - जल निकासी हेतु पक्की ईंटों की नालियाँ होती थी । विश्व की किसी अन्य सभ्यता में पक्की नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते थे ।

प्रमुख नगर

हडप्पा सभ्यता

- चार्ल्स मेसन – 1826 ई. सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया ।
- जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन – 1856 ई हडप्पा नगर का सर्वे किया ।
- कनिंघम ने इस सभ्यता की ओर ध्यान दिलाया । कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है ।
- 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया ।
- सर्वप्रथम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हडप्पा सभ्यता कहलाया ।
- यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ।
- उत्कृष्ट नगर व्यवस्था एवं जल निकासी व्यवस्था इसको विशिष्ट बनाती है ।
- पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित (अब – शाहीवाल जिले में) रावी नदी के तट पर
- उत्खननकर्ता – दयाराम साहनी
- रावी नदी के तट पर श्रमिकों के आवास एवं अन्नागार मिलते हैं ।

- R – 37 नामक कब्रिस्तान मिलता है । एक शव को ताबूत में दफनाया गया है, इसे विदेशी की कब्र कहते हैं ।
- टीले पर निर्मित – व्हीलर ने "माउण्ट A – B" कहा
- शंख का बना बैल 18 वर्ताकार चबूतरे मिले हैं ।
- यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली है ।
- 6 – 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों वाला आवास स्थल मिला है ।
- नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे अर्थात् शतरंज के बोर्ड की तरह सभी नगरों को बसाया था । सभी मार्ग समकोण पर काटते थे ।
- एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मृणमूर्ति मिली है । सम्भवतः उर्वरता की देवी होगी ।

मोहनजोदड़ों

स्थिति = लरकाना (सिन्ध, PAK)
सिन्धु नदी के तट पर
उत्खननकर्ता = राखलदास बनर्जी
मोहनजोदड़ों का शाब्दिक अर्थ = मृतकों का टीला (सिन्धी भाषा) ।

विशाल स्नानागार

- 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर ।
- सम्भवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा ।
- सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है ।
- विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बडी इमारत है । लम्बाई 45.71×15.23 मीटर चौडी है ।
- महाविद्यालय के साक्ष्य
- सूती कपडे के साक्ष्य
- हाथी का कपालखण्ड
- काँसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है ।
- पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है । इसने शॉल ओढ रखी है जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है ।
- यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है ।
- योगी की मूर्ति मिली है ।
- आद्य शिव की मूर्ति मिली है ।
- बाँध से पतन के साक्ष्य मिलते है ।
- सर्वाधिक मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है ।

लोथल

- स्थिति - गुजरात
- भोगवा नदी के किनारे
  उत्खननकर्ता - S. R. राव (रंगनाथ राव)
- यह एक व्यापारिक नगर था ।
- यहाँ से गोदीवाडा (Dockyard) मिलता है ।
- यह सिन्धु घाटी सभ्यता की सबसे बडी कृति है ।
- मनके (Bead) बनाने का कारखाना
- चावल के साक्ष्य
- फारस की मुहर जो गोलाकार बटनुमा है ।
- घोडे की मृण्मूर्तियाँ
- चक्की के दो पाट
- घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं । (एकमात्र लोथल में)
- छोटे दिशा सूचक यंत्र

सुरकोटडा/सुरकोटदा

- स्थिति - गुजरात
- उत्खनन कर्ता – जेपी जोशी
- घोडे की हड्डियाँ
- सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगों को घोडें का ज्ञान नहीं था ।

रोजदी (गुजरात)

- हाथी के साक्ष्य

रोपड (पंजाब)

- मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य ।

धौलावीरा

- गुजरात – कच्छ जिला (किसी नदी तट पर नहीं)
- उत्खननकर्त्ता – रविन्द्र सिंह विष्ट (1990 में)
- यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया ।
- कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य । संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते होंगे । (दुर्गाभाग, मध्यम नगर, निचला)
- यह नगर 3 भागों में बँटा हुआ था ।
- स्टेडियम एवं सूचना पट्ट के अवशेष मिलते है । (खेल का मैदान)

चन्हुदड़ों

- उत्खननकर्त्ता – एन. मजूमदार (डाकूओं ने हत्या कर दी) – अर्नेस्ट मैके

भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने के लिए आये थे इन्होंने भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था ।

बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर, 1764) के बाद प्रथम बार 1765 में कम्पनी को बंगाल, बिहार व उडीसा की दीवानी प्राप्त हुई ।

दीवानी – दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति ।

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

1. इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया । उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् बनाई गई । प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था ।
2. बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे ।
3. इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश थे ।
4. कम्पनी सर्वोच्य सत्ता (गवर्निंग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया । उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए । भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी ।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

1. इसमें कम्पनी के वाणिज्य एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया ।
2. इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मण्डल को वाणिज्य कार्यो की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यो के लिए board of central बनाया ।
3. भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिसम्पत्ति के सैन्य एवं नागरिक कार्यो पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ सेन्ट्रल नियंत्रक मण्डल को दी ।
4. प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया Board of control व court of directors
5. भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा ।

1833 चार्टर एक्ट

1. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया । सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमें निहित की गई । भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग थे ।
2. गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार दिये । इनके द्वारा कानून नियामकों को कानून कहा गया तथा नये कानूनों के तहत बनाये गये कानूनों को अधिनियम या Act कहा गया ।
3. बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई सारी शक्ति बंगाल में गठित थी ।
4. ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला । यह व्यापारिक कम्पनी नही रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी ।
5. प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियों में आधार बनाने का असफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदो के उपयुक्त माना गया ।
   इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा ।

1853 A.D. का चार्टर एक्ट

1. इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी और कार्यपालिका कार्यो को अलग किया तथा 6 नये सदस्य जोडे गये जिन्हे विधायी पार्षद कहा गया । अर्थात् गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद् बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद् कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमें वही प्रक्रियाये अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी ।
2. भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया ।
3. सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की सेवाये थी
   1. उच्च Candidate से बात
   2- निम्न Unconventade

इस एक्ट में उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई ।

यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयावधि नही दी गई ।

1858 का भारत शासन अधिनियम

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त किया गया तथा सारी सत्ता ब्रिटिश राजमुकुट (क्राऊन) के अन्तर्गत आ गई इस अधिनियम को act for the golden government of india भारत की इच्छा सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम कहते है ।

1. भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा ।
2. भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ।
   - वह भारत में ब्रिटिश राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधि था ।
   - प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था ।
3. Bord वह Control तथा Court of Director समाप्त का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया ।
4. एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretary of state for india) का सर्जन किया गया ।
   - सम्पूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था ।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य समिति बनाई गई ।
   - इसमें सलाहकार कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से था । 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत का सचिव था ।
6. यह समिति नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इग्लैण्ड में मुकदमें में एक पक्ष बनाने का अधिकार था अर्थात् यह किसी पर मुकदमा कर सकती थी तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था । इनका ऑफिस ब्रिटेन में ही था ।

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को शासन में भारतीयों का सहयोग आवश्यक लगा अतः उक्त अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गये ।

1. वायसराय की विस्तारित परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन सम्भव हुआ । 1862 में प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों – बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को नामांकित किया ।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विधायी शक्तियाँ वापस मिली अर्थात् विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरूआत हुई ।
3. इसके माध्यम से बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त परिषदों का गठन हुआ ।
4. इसमें वायसराय को परिषद् में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की स्वतंत्रता दी ।
   1859 में लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली मंत्रालय को मान्यता दी अर्थात् वायसराय की परिषद् का कोई सदस्य एक या अधिक सरकारी का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे परिषद् के ओर से अन्तिम आदेश पारित करने का अधिकार था ।
5. इसमें आपातकाल में वायसराय को विधायी परिषद् की सलाह के बिना आध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी ।

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

1. इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढाई गई किन्तु बहुमत सरकारी सदस्यों का था ।
2. इसमें विधानपरिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई । जैसे – बजट पर चर्चा का अधिकार, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार ।
3. इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद् के गैर सरकारी सदस्यों का माननीय प्रान्तीय विधान परिषद् तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन विश्वविद्यालय जिला बोर्ड व्यापार संघ नगरपालिका तथा जमींदारो के द्वारा किया जाना था । अन्तिम निर्णय वायसराय गवर्नर का होता था ।

यद्यपि उक्त अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक समिति एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया ।

1909 का भारत शासन अधिनियम

इसे मॉर्ले–मिन्टो सुधार कहते है ।

लार्ड मार्ले भारत सचिव था तथा लार्ड मिन्टो भारत का वायसराय था ।

विशेषता

1. इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई (60) । राज्यों में संख्या अलग अलग थी ।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई ।

3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारोंमें दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई जैसे – पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि ।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद् के सदस्य बनने की अनुमति मिली सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद् में विधि सदस्य बनाया गया ।
5. मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल Separate Electorate की बात की गई ।

1919 का भारत शासन अधिनियम

20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका ध्येय भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा ।

- इसी आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं ।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथा चेम्सफार्ड भारत का वायसराय था (मोन्ट फोर्ड एक्ट)।

विशेषता

1. केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ । यद्यपि राज्यो का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है ।

2. प्रान्तीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया – आरक्षित और हस्तान्तरित ।
   - हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियो के माध्यम से शासन करेगा ।
   - आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से बिना विधायी परिषद् के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात् यह एक द्वैध शासन था ।
   - विधायिका में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था ।

3. इस अधिनियम में पहली बार द्वि–सदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद् के दो सदन थे – लेजिस्लेटिव असेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा) दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे । महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया ।
4. शिक्षा कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया ।

5. वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यो में से कमांडर इन चीफ को छोडकर तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था । इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एंग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया ।

6. लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजन किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया ।

7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया । उच्च नागरिक सेवाओं के लिए गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।

8. केन्द्रीय बजट को राज्यो के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओ को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये ।

9. इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा ।

कमियाँ

1. कोई भी प्रान्तीय दल गवर्नर की स्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए रोका जा सकता था ।
2. यद्यपि प्रान्तों को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह संघात्मक शक्ति वितरण नहीं था क्योंकि यह पृथक केन्द्र, द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी ।
   - केन्द्रीय विधानपरिषद् भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी ।
3. केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं थी । वायसराय भारत सचिव का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था ।
4. अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नहीं की जा सकती थी ।
5. वित्त एक आरक्षित विषय था जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य के अधीन था अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ पाता था ।

6. ICS के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियों को अपनी नीतियाँ क्रियान्वित करनी थी, वे भारत सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथा मंत्रियों के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरदायी थे ।
7. भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री उस समय लॉयड जार्ज था ।

1920 A.D. ने मद्रास में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

नोट –

भारत शासन अधिनियम 1935

1. इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिससे प्रान्तों और रियायतों को सम्मिलित किया तीन सूचियाँ बनाई गई ।
   1. केन्द्रीय सूची 59 विषय
   2. प्रांतीय सूची 54 विषय
   3. समवर्ती सूची 36 विषय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई ।

   यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियायतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया ।
2. प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्तता प्रारम्भ हुई राज्य सूची के विषयों में स्वंतत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिका के लिए जबाबदेही थे ।
3. संघीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।
   - संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित में विभक्त किया गया ।
   - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदो जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियों के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद् के लिए उत्तरदायी थे ।
4. इसमें 11 में से 6 प्रान्तों में द्विसदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की

   1. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त उच्च सदन को विधानपरिषद् (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कहा व निम्न सदन को विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
5. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढाया गया । दलित महिलाओं एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये ।
6. 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद् को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारो का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
7. मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया ।
8. संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
9. भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गयी ।
10. संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 में गठित हुआ । इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा संविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है । महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

भारत शासन अधिनियत 1947

3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउन्ट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे माउन्ट बेटन योजना कहते है ।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विशेषताएँ थी –

1. भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वंतत्र एवं सम्प्रभू राष्ट्र घोषित किया गया ।
2. इसमें भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी ।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन केबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी । ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था ।
4. इसके माध्यम से दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला ।
5. इसने दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नही हो जाता तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेगी । 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा घोषित पारित कोई भी

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था के पिता – एडम स्मिथ ।
(Wealth of Nation)

किसी देश में होने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपनायी गई व्यवस्था, नियम, नीतियाँ उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है ।

अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती हैं –

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था
   - यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों और सम्पत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का नियंत्रण हो तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है ।
   - सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज कल्याण होता है ।

2. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
   - इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और सम्पत्तियों पर निजी व्यक्तियों/निजी क्षेत्रों का नियत्रंण होता हैं ।
   - इस अर्थव्यवस्था में व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है ।

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था
   - इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद व पूँजीवाद दोनों के लक्षाण पाये जाते हैं अर्थात् उत्पादन के साधनों और सम्पत्तियों पर सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है ।
   - भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है ।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

अर्थव्यवस्था के कुल पाँच क्षेत्र माने जाते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले क्षेत्र मात्र तीन ही होते हैं ।

1. प्राथमिक क्षेत्र
   - इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से आर्थिक कार्य किये जाते हैं । सामान्यतः इस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है । जैसे– कृषि, वन, मछली पालन आदि ।
   - इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ।

2. द्वितीयक क्षेत्र
   - निर्माण, विनिर्माण, उत्पादन आदि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ मानी जाती हैं ।
   - इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है ।
   - खनन, उत्खनन, बिजली उत्पादन आदि भारत में द्वितीयक क्षेत्र में लिये जाते हैं ।

3. तृतीयक क्षेत्र
   - इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है ।
   - इस क्षेत्र में केवल सेवाएँ शामिल की जाती है । जैसे– डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए आदि ।

क्षेत्र	GDP में योगदान	रोजगार में योगदान
कृषि	17%	50%
उद्योग	25%	25%
सेवा	$\frac{58}{100}$ %	$\frac{25}{100}$ %

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 25% भाग उद्योग क्षेत्र से आता है ।
- भारत की जनसंख्या का लगभग 25% भाग रोजगार के लिए उद्योगों पर निर्भर है ।

1. पहली औद्योगिक नीति
   - यह नीति 1948 में जारी की गई ।
   - यह नीति डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई ।
2. दूसरी औद्योगिक नीति
   - यह नीति 1956 में जारी की गई ।
   - यह नीति पी. सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ।
3. तीसरी औद्योगिक नीति
   - इसे डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा जारी किया गया ।
   - सरकार द्वारा केवल तीन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे गये ।
     (i) परमाणु ऊर्जा (ii) परमाणु खनिज
     (iii) रेलवे

राष्ट्रीय आय

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है अर्थात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है ।
- राष्ट्रीय आय के लिए आँकड़ों का संकलन NSSO & CSO द्वारा किया जाता है ।
- यह दोनों संस्थाएँ MOSPI के अन्तर्गत कार्य करती है ।
  MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)
  NSSO = National Sample Survey Office
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है–
  (i) आय विधि
  (ii) व्यय विधि
  (iii) उत्पाद विधि
- भारत में मिश्रित विधि का उपयोग किया जाता है ।
- कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है ।
- सेवा क्षेत्र के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है ।
- भारत व्यय विधि का उपयोग नहीं करता है ।
- भारत में 2011–12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित हैं– GDP, GNP, NDP, NNP ।
- भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पाद विधि के आधार पर किया जाता है ।
- जनवरी, 2015 से CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना 'बाजार मूल्य (Market Price)' पर की जाती है ।

बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{mp})

1. GDP, एक देश की घरेलू सीमा में, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य ।
2. सभी निवासी तथा गैर निवासी के द्वारा उत्पादन को शामिल किया जायेगा, चाहे वह कंपनी घरेलू हो या विदेशी ।
3. GDP_{mp} = C + I + G + X – M = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात–आयात ।

साधन लागत पर GDP_{FC}

1. साधन लागत पर GDP, बाजार कीमतों पर GDP में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है ।
2. बाजार कीमतें वही किमतें हैं जो उपभोक्ता द्वारा दी जाती है । इसमें उत्पाद करों तथा उपदानों को भी शामिल किया जाता है ।
3. 'साधन लागत' शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है, इसमें बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करो को घटाने पर प्राप्त होती है ।
4. साधन लागत पर GDP एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों द्वारा किये गये उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है ।
   = $GDP_{FC} = GDP_{MP} – NIT$

वित्त वर्ष

- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूँढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया –
  1. बेल्बी आयोग
  2. L. K. JHA समिति
  3. दार्निश वाचा समिति
  4. शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)
- भारत की GDP गणना अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे GVA (सकल मूल्य संवर्द्धन) आधारित बनाया गया ।
  1. GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit
  2. $GVA_{bp} = GVA_{fc}$ + उत्पादन कर – उत्पादन Subsidy
  3. $GDP_{mp} = GVA_{bp}$ + उत्पाद कर – उत्पाद Subsidy
- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते हैं, आधार मूल्य कहलाता है ।

बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद = (NDP)

सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है ।

$NDP_{MP} = GDP_{MP} – Depreciation$

साधन/स्थायी लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{FC})

साधन लागत पर NDP उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है ।

$NDP_{FC} = NDP_{MP}$ – निवल उत्पाद कर – निवल उत्पादन कर ।

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यही भारत की राष्ट्रीय कर साध या स्थायी कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि

GVA_{MP} = निविल उत्पादन कर

उत्पादन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि

आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि – निविल उत्पादन कर

GVA = Gross Value Adde सकल मूल्य वृद्धि

मूल्य ह्रास – उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है ।

बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP})

1. एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य GNP_{MP} है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है ।
2. देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है चाहे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के अन्दर उत्पादन करें या विदेशी सीमा में ।

सामाधान /स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP_{MP}

साधन लागत पर GNP एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है ।

बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP})

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है ।

$NNP_{MP} = GNP_{MP}$ – DEP (मूल्य ह्रास)

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{FC})

साधन लागत पर NNP एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है ।

यह राष्ट्रीय उत्पाद है किन्तु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह शुद्ध घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का योग है ।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NNP)

- $NNP_{fc} = NNP_{mp}$ – अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$ $\frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp}$ – मुद्रास्फीति (CP = स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक GDP भी कहा जाता है ।
- बाजार मूल्य पर GDP को Nominal GDP भी कहा जाता है ।
- GDP Deflator = $\frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} / \frac{GDPmp}{GDPcp}$

मुद्रास्फीति (Inflation)

- किसी देश/अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढना मुद्रास्फीति कहलाता है ।
- मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है अर्थात् महँगाई का बढना या रुपये के मूल्य में गिरावट मुद्रास्फीति कहलाता है ।

मुद्रास्फीति का भारतीय सन्दर्भ में विशेष प्रभाव –

1. कराधान में वृद्धि
2. आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में ह्रास
3. बचतों में कमी
4. बैंकिंग व बीमा उद्योगों का विकास
5. नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली
6. धन का पुनः वितरण
7. सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि